

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1930
दिनांक 11.03.2025 को उल्तरार्थ

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना

+1930 श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी:

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या ई-पंचायत मिशनमोड परियोजना (एमएमपी) के अंतर्गत प्रदान की गई डिजिटल अवसंरचना प्रयोक्ता-हितैषी है और यह देश में विशेष कर दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायतों में आसानी से उपलब्ध है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या सरकार का भविष्य में ई-पंचायत मिशनमोड परियोजना में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) देश में ई-पंचायत मिशनमोड परियोजना के अंतर्गत राज्य-वार विशेष कर मध्य प्रदेश में डिजिटली कृत की गई पंचायतों की संख्या कितनी है;
- (घ) क्या देश में राज्यवार विशेष कर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में शेष पंचायतों के डिजिटली करण हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और
- (ङ) पंचायतों के डिजिटली करण के माध्यम से प्रशासन और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी में कितना सुधार होने की उम्मीद है?

उल्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ङ) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य पंचायतों के कामकाज में सुधार लाना और उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। मंत्रालय ने पंचायत की आयोजना, लेखांकन और बजटन जैसे कार्यों को सरल बनाने के लिए एक लेखांकन एप्लिकेशन ई-ग्रामस्वराज शुरू किया है। मंत्रालय ने विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने हेतु ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-ग्रामस्वराज को भी एकीकृत किया है। वर्ष 2024-25 के लिए ई-ग्रामस्वराज के तहत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति **अनुबंध-1** में दी गई है।

मंत्रालय ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को निरंतर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त फीडबैक और इनपुट के आधार पर, विभिन्न एप्लिकेशनों में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पंचायत अधिकारियों और हितधारकों के बीच डिजिटल साक्षरता को

मजबूत करने के लिए क्षमता-निर्माण की पहल की जा रही है जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावपूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके।

मंत्रालय ने पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवा प्रदायगी को बढ़ाने के लिए सर्विसप्लस को भी लागू किया है। यह समनुरूप/कॉन्फ़िगर करने योग्य प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के तेजी से लागू करने में सक्षम बनाता है। यह प्लेटफॉर्म 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 3,606 से अधिक सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है, वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करता है, पारदर्शिता बढ़ाता है और दक्षता सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, मंत्रालय ने स्थानीय कार्यों को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित करते हुए आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर भी प्रस्तुत किया है। यह फ्रेमवर्क नागरिकों की शिकायतों का प्रभावी समाधान करते हुए समयबद्ध तरीके से सेवाएं देने में पंचायतों का मार्गदर्शन करता है। वर्ष 2021 में आयोजित अभियान "मेरी पंचायत, मेरा अधिकार - जन सेवाएँ हमारे द्वार" ने इन प्रयासों को मजबूत किया है। अब तक, 2.15 लाख ग्राम पंचायतों ने अपने नागरिक चार्टर अपलोड किए हैं, जो 954 प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, डिजिटल इंडिया के विजन को प्राप्त करने के लिए, भारतनेट परियोजना को दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। अब तक कुल 2.68 लाख ग्राम पंचायतों/पारंपरिक स्थानीय निकायों (TLB) में से 2.18 लाख ग्राम पंचायतों/पारंपरिक स्थानीय निकायों को भारतनेट परियोजना के तहत हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने हेतु सेवा के लिए तैयार किया गया है। डिजिटल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए, भारतनेट चरण- I और चरण- II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन और शेष ग्राम पंचायतों में नेटवर्क के निर्माण के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को 04.08.2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। बीएसएनएल को परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

पंचायतों के डिजिटलीकरण से शासन और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी में महत्वपूर्ण सुधार आने की उम्मीद है। मुख्य लाभों में वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि, कुशल आयोजना और बजटन, निबंध रूप से डिजिटल रिकॉर्ड रखना और ग्रामीणों के लिए सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुँच शामिल है। पीएफएमएस के साथ एकीकरण समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है, देरी को कम करता है और वित्तीय दक्षता को बढ़ाता है। कुल मिलाकर, ई-पंचायत एमएमपी जगीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है और पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बना रहा है।

‘ई-पंचायत मिशनमोड परियोजना’ के संबंध में दिनांक 11.03.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1930 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायत स्तर पर अपनाई गई ई-ग्रामस्वराज परियोजना

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्र म पंचायतों की कुल संख्या एवं समकक्ष	ऑनबोर्ड ग्र म पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्र म पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या और समकक्ष	ऑनबोर्डब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वालीब्लॉक पंचायतें	जी ला पंचायतों की कुल संख्या और समकक्ष	ऑनबोर्ड जीला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली जीला पंचायतें
1	आंध्रप्रदेश	13328	13296	12970	660	660	642	13	13	13
2	अरुणाचलप्रदेश	2108	2106	222	0	0	0	27	25	8
3	असम	2662	2197	2176	191	191	189	30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8045	534	534	530	38	38	38
5	छत्तीसगढ़	11596	11594	11516	146	146	146	27	27	27
6	गोवा	191	190	93	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	14656	14599	13890	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6226	6222	5914	143	143	134	22	22	22
9	हिमाचलप्रदेश	3615	3614	3540	81	81	81	12	12	12
10	झारखंड	4345	4345	4329	264	264	262	24	24	24
11	कर्नाटक	5954	5954	5937	238	232	126	31	31	28
12	केरल	941	941	941	152	152	152	14	14	14

सं. अ. सं.	राज्य का नाम	ग्र म पंचायतों की कुल संख्या एवं समकक्ष	ऑनबोर्ड ग्र म पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्र म पंचायतों और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या और समकक्ष	ऑनबोर्डब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वालीब्लॉक पंचायतों	जीला पंचायतों की कुल संख्या और समकक्ष	ऑनबोर्ड जीला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वालीजीला पंचायतों
13	मध्यप्रदेश	23011	23009	22980	313	313	310	52	52	52
14	महाराष्ट्र	27917	27894	26737	351	351	307	34	34	34
15	मणिपुर	3180	161	123	0	0	0	12	6	4
16	मेघालय	6817	0	0	2241	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	842	842	832	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	1289	186	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	6793	314	314	314	30	30	30
20	पंजाब	13237	13222	9775	152	151	114	22	22	19
21	राजस्थान	11211	11207	10837	361	353	351	33	33	33
22	सिक्किम	199	199	195	0	0	0	6	6	6
23	तमिलनाडु	12525	12525	12519	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	12991	12768	12636	572	540	508	32	32	32
25	त्रिपुरा	1194	1185	1174	75	75	75	9	9	9
26	उत्तराखण्ड	7795	7794	7743	95	95	95	13	13	13
27	उत्तरप्रदेश	57691	57691	57609	826	826	818	75	75	75
28	पश्चिमबंगाल	3339	3339	3338	345	345	345	22	21	21
कुल		263708	251928	242864	8690	6402	6135	652	642	612
